विपुल राम (कथा) में कृष्ण (पाल) न आये

फ़रीदाबाद (म.मो.) नवचेतना ट्रस्ट द्वारा आयेजित 9 दिन तक चली मुरारी बापू की राम कथा सुनने, बापू का आशीर्वाद लेने तथा अपना खुद का प्रवचन झाड़ने बहुतेरे नेता आये, परन्तु स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर नहीं फटके। उन्हें शायद बापू के आर्शीवाद की जरूरत महसूस नहीं हुई। हो सकता है उन्हें अपने कर्मों व भाग्य पर पूरा भरोसा हो।

विदित है कि सेक्टर 12 स्थित 'हूडा' के सरकारी मैदान में इस कथा का ओयाजन किया गया था। इसका उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी व समापन मुख्यमंत्री खट्टर ने किया था। इस बीच राज्य के गर्वनर कप्तान सिंह सोलंकी व पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा सहित अनेकों नेता बापू की चरणवंदना करने एवं आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। कथा सुनने वालों की भीड़ का लाभ उठाते हुये लगभग सभी नेतागण भी अपने अंदाज में अपनी-अपनी बात कह गये।

लेकिन स्थानीय सांसद एवं मंत्री कृष्णपाल गूजर ने कथा सुनना या आशीर्वाद लेना तो दूर इस तरफ़ झांक कर भी नहीं देखा। यहां तक कि प्रोटोकॉल के नाते मुख्यमंत्री व गर्वनर की अगवानी करने तक भी नहीं पहुंचे। इसका कारण उद्योग एवं पर्यावरण मन्त्री विपुल गोयल व कृष्णपाल के बीच रहने वाला 36 का आंकड़ा समझा जा रहा है। सुधी पाठक गतांक में पढ चुके हैं कि इस कथा का आयोजन जिस नवचेतना ट्रस्ट ने किया है उसका पूरा नियन्त्रण विपुल गोयल के हाथों में है।

शहर में यह चर्चा तो बहुत पहले से ही थी कि किसी जमाने में कृष्णपाल के खासमखास रहे विपुल विधायक बनने के बाद उन से दूर हटने लगे। हटते भी क्यों नहीं, क्योंकि पुरानी दोस्ती बराबरी पर आधारित नहीं थी। कृष्णपाल राजनीति के काफ़ी ऊंचे पायेदान पर थे और विपुल की उनके सामने कोई हैसियत न थी, परन्तु विधायक बनने के बाद जब विपुल की हैसियत भी बढने लगी तो कृष्णपाल को यह अखरने लगा। कृष्णपाल के पुरज़ोर विरोध के बावजूद जब विपुल न केवल कैबिनेट मन्त्री बन गये बल्कि उद्योग एवं पर्यावरण जैसे मलाईदार महकमे भी ले लिये। इससे इन दोनों के बीच की खाई दिन दूणी रात चौगुणी होती चली गयी। यही कारण है कि इन दोनों नेताओं को कभी भी किसी आयोजन में साथ-साथ नहीं देखा जाता।

कहने को दोनों भाजपाई हैं और एक दूसरे से बढ़कर मोदी भगत भी हैं। भाजपा एवं मोदी दोनों से ही अपेक्षा करते हैं कि अपने निहित स्वार्थों को त्याग कर एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करते हुए इसे आगे बढायें। परन्तु दोनों पेशेवर नेताओं के लिये निहित स्वार्थ पहले और पार्टी हित बाद में आता है। जिसकी भी राजनीतिक दुकान बंद हो गयी या मंदी पड़ गयी, उसे पार्टी की मजबूती से क्या लेना-देना? इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेता अपनी-अपनी चौधर एवं दुकानदारी चमकाने को सर्वाधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। जाहिर है इसका असर आगामी चुनावों में भी देखने को मिलेगा।

राम कथा के बहाने भाजपा के भीतर विपुल गोयल व कृष्णपाल के आपसी मतभेद तो खुल कर आये सो आये। इसके अलावा कथावाचक मुरारी व मुख्यमंत्री खट्टर ने एक स्वर में राष्ट्र धर्म व युगधर्म का संदेश दिया। दोनों ने ही माना कि केवल सड़कें, सीवर व भवन आदि जैसे भौतिक निर्माणों को विकास नहीं समझना चाहिये। व्यक्तियों का व्यक्तिगत बौद्धिक एवं उनके चरित्र का विकास ही असली विकास है। आपसी भेद-भाव जात-पांत आदि का भेद मिटा कर एकजुट होकर देश का विकास करना चाहिये।

बातें तो वास्तव में ही सुन्दर कही। लेकिन व्यक्ति का विकास होगा कैसे? सरकारी स्कूलों का परिणाम तो ज़ीरो प्रतिशत आ रहा है। पढाने को मास्टर नहीं हैं स्कूलों में। स्कूलों को बंद करने की योजना पर खट्टर सरकार पूरा काम कर रही है। शिक्षकों की तैनाती को लेकर लड़कियां धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विकास होगा कैसे? क्या राम कथा सुनने मात्र से विकास हो जायेगा? रही बात चरित्र निर्माण की तो तमाम भाजपा सरकारों को चलाने वाले विधायकों, सांसदों, मन्त्रियों व इनके अफ़सरों की काली करतूतें जनता रोज़ाना देख ही रही है। उन्हें देख-सीख कर जैसा चरित्र निर्माण हो रहा है वह सबके सामने है।

चार साल बाद आखिर यमुना पुल निर्माण शुरू

टोल भी नहीं लगेगा - क्या सचमुच?

गडकरी : घोषणा जल्दी करी

गूजर : मुसीबत सिर पड़ी

फ़रीदाबाद (म.मो.) 15 अगस्त 2014 को स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने, केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से मंझावली स्थित यमुना पुल की आधारशिला रखवाई थी। इससे करीब 20-25 वर्ष पूर्व तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री राजेश पायलेट ने भी यही काम किया था। जवाब में कृष्णपाल तथा गडकरी ने दावा किया था कि वे तो मात्र 2 साल में इस पुल को चालू कर देंगे। उस वक्त '**मज़दूर मोर्चा**' ने लिखा था कि चालू करना तो दूर 2 साल में यदि यह सरकार पुल की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) भी बना लेगी तो बड़ी बात होगी। जुमलेबाज़ों की सरकार के बारे में '**मज़दूर मोर्चा**' का वह आकलन शत प्रतिशत से भी अधिक सही साबित हुआ।

यदि सरकार ने पुल निर्माण का कार्य जून 2018 में ही चालू करना था तो 15 अगस्त 2014 को उतनी भारी-भरकम ड्रामेबाज़ी क्यों की थी? उस दिन वाली आधारशिला को अब रख लेते। दरअसल आधारशिला का तो बहाना था। गूजर को उस वक्त सिर पर आये विधान सभा चुनावों के लिये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। टिकट के लालच में बहुत लोग बेवकूफ़ बने जो बसें व ट्रालियां भर-भर कर उस ड्रामे में लाये थे।

इस पुल के बारे में कृष्णपाल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा यह की है कि इस पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। वैसे मोदी व उसके भक्तों की किसी बात पर अब सहज यकीन नहीं होता। कृष्णपाल की इस बात पर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। सच्चाई बहुत देर तक छिपने वाली नहीं है, बहुत जल्दी सामने आ जायेगी।

गूजर के मुताबिक इसी वर्ष 31 दिसम्बर तक यह पुल बन कर तैयार हो जायेगा। 'मज़दूर मोर्चा' का मानना है कि इस वर्ष की बजाय यदि अगले वर्ष यानी 31 दिसम्बर 2019 तक भी यह पुल बन कर तैयार हो जाय तो बहुत बड़ी बात है।

इस पुल के देरी से बनने के चलते लोग़ों को जो दिल्ली होकर नोयडा आना-जाना पड़ता है उससे करोड़ों रुपये रोजाना का खर्च तो होता ही है कीमती समय जो बर्बाद होता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। इसके अलावा पर्यावरण में पैट्रोलियम का धुंआ घुल रहा है वह अलग से। सुधी पाठक समझ सकते हैं 5-6 वर्ष की इस देरी से कितनी भारी क्षति इस देश को हो चुकी है।

बदरपुर टोल पर बोलते हुये मंत्री गूजर ने कहा कि यह जजिया कांग्रेस की देन है। कांग्रेस सरकार ने पुल निर्माता कम्पनी से जो एग्रीमेंट कर रखा था उसे वे तोड़ नहीं सकते। तो क्या गूजर महोदय को इस बात का ज्ञान अब मंत्री बनने के बाद हुआ है? जब वे 2014 के चुनाव से पहले इसी टोल पर हंगामा करने पहुंचे थे और इस टैक्स को जजिया बताते हुए अपनी सरकार आने पर हटाने का वायदा कर रहे थे तो इतने अज्ञानी एवं मूर्ख थे कि उन्हें उस एग्रीमेंट की समझ ही नहीं थी? दरअसल समझ तो सारी थी परन्तु भारतीय जुमला पार्टी का यही एजेंडा रहा है कि जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। जब नरेन्द्र मोदी 15-15 लाख रुपये हर नागरिक को देने का जुमला फ़ेंक सकता था तो कृष्णपाल टोल जजिया हटाने का क्यों नहीं।

सरकारी स्कूलों के जीरो से तीस परसेंट परिणामों को लेकर 'जांच' का नाटक

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते पखवाड़े हरियाणा सरकार के स्कूलों के 10 वीं तथा 12 वीं के परिणाम 0 से लेकर 30 परसेंट तक आने को लेकर सरकार हैरान व परेशान दिखने का ढोंग करते हुए इसकी जांच कराने के नाम पर एक और पाखंड करने जा रही है। खट्टर सरकार ऐसे दिखावा कर रही है मानो उनकी अपेक्षा तो 90 से 99 परसेंट तक की थी और परिणाम आ गये 0 से 30 परसेंट।

वास्तव में पता तो सब को था कि परिणाम तो यही आयेंगे। जहां कहीं 30 परसेंट आ भी गये हैं वह छात्रों व उनके अभिभावकों के निजी प्रयासों से ही आ पाये हैं; वरना सरकार ने तो पूरा प्रोग्राम 0 परसेंट का ही बना रखा था। कौन नहीं जानता कि आधे से अधिक स्कूलों में हैडमास्टर अथवा प्रिंसिपल ही नहीं हैं। पढाने वाले शिक्षकों के आधे से अधिक पद दसियों वर्ष से रिक्त पड़े हैं, जो शिक्षक हैं भी उनमें भी अधिकांश शिक्षक न होकर 'अतिथि' हैं। सोचने समझने की बात है कि अतिथि तो अतिथि ही होता हैं उनसे किसी काम की अपेक्षा की ही नहीं जानी चाहिये।

परीक्षा परिणाम 0 परसेंट क्यों न हो जब स्कूलों में बाकी सब कुछ तो होता है बस केवल पढाई ही नहीं होती। पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव कराने हों तो स्कूल मास्टरों को बुला लो। केवल चुनाव ही नहीं मतदाता सूचियां बनाने व उन्हें ठीक करने वाला साल भर चलने वाला सारा काम मास्टर जी ही तो करते हैं। इसी सम्बन्ध में बीएलओ (ब्लॉक लेवल अधिकारी) का पद भी स्थाई रूप से मास्टरों को दे दिया गया है।

जनगणना हो या पोलियो अभियान या पर्यावरण तथा एड्स रैलियां निकालनी हों तो पकड़ लाओ मास्टरों को। यानी सरकार की नज़र में स्कूल मास्टर ही एक ऐसा निरीह प्राणी समझा गया है कि जिसके पास करने को कोई काम नहीं है, क्योंकि पढाने को तो वे काम ही नहीं समझते। इस लिये जब भी ज़िला प्रशासन को किसी काम के लिये अतिरिक्त स्टाफ़ की जरूरत पड़ती है पेल देते हैं मास्टरों को।

इस बाबत जब भी शिक्षा अधिकारी एसडीएम या डीसी को बच्चों की पढाई के नुकसान की बात करते हैं तो उन्हें बुरी तरह से डांट दिया जाता है। कोई शिक्षा अधिकारी कुछ ज़्यादा बोलने का प्रयास करे तो उसे एफ़आईआर दर्ज कराने तक कि धमकी भी दे दी जाती है। संदर्भवश एक समय यहां उपायुक्त रहे डॉक्टर राकेश गुप्ता की याद आ गयी। उनके सामने ज़िला के कुछ शिक्षा अधिकारी बताने पहुंचे कि दर्जनों मास्टर गत कई माह से स्कूल नहीं आ रहे हैं। पूछने पर कहते हैं कि वे डीसी ऑफ़िस में बने चुनाव दफ़्तर में जाते हैं। इससे बच्चों की पढाई का काफ़ी नुक्सान हो रहा है। इस पर डीसी राकेश गुप्ता ने कहा कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो किसी भी अन्य काम से जरूरी है। यदि कोई इसमें कोताही करेगा तो उसके विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अपने कार्यालय में केवल आधा स्टाफ़ तैनात है तो क्या वे दफ़्तर बंद कर दें? काम बंद नहीं हुआ करते, काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा था साहब बहादुर ने, इसी लिये काम तो चल रहे हैं और परिणाम 0 से 30 परसेंट आ रहे हैं। जाहिर है ऐसे काम चलने से तो ऐसे ही परिणाम आते हैं।

इतना ही नहीं बहुत से मास्टर स्कूल में समय 'बर्बाद' करने की अपेक्षा विधायकों, सांसदों व मंत्रियों की सेवा एवं चापलूसी में समय बिताना ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं। ऐसे हरामखोरों के विरुद्ध जब कोई शिक्षा अधिकारी थोड़ी-बहुत कार्यवाही करने का प्रयास करता है तो उनके गॉडफ़ादर बने नेता झट से सामने आ खड़े होते हैं। वे अधिकारियों को धमकाते हैं और यदि कोई धमकाने से भी न माने तो उसका तबादला करा दिया जाता है। ऐसे माहौल में कोई भी अधिकारी इन हरामखोरों से पंगा लेने का साहस नहीं करता। ऐसे में हरामखोर मास्टर और भी तत्परता एवं उत्साह से बच्चे पढाने की बजाय नेताओं की चाकरी करना श्रेयस्कर समझते हैं।

तथ्य सारे सामने हैं। सरकार को जांच का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जनता सब कुछ देख व समझ रही है।

नहर पार की सोसायटियों के विरुद्ध फ़िर प्रदूषण विभाग का खटराग

फ़रीदाबाद (म.मो.) नहर पार बसे ग्रेटर फ़रीदाबाद में बसी दर्जनों रिहायशी सोसायटियों के विरुद्ध प्रदूषण विभाग एक बार फ़िर से सक्रिय हो उठा है। इन फ़्लैटों में रहने वाले लाखों निवासियों को विभाग ने नोटिस जारी कर उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटने की धमकी दी है। इनका कसूर यह बताया गया है कि इनका सीवेज बाहर खुले मैदान में जगह-जगह एकत्र हो रहा है।

विदित है कि सीवरेज व्यवस्था नहीं होने के चलते सोसायटियों के निवासी महंगे दाम देकर ट्रैक्टर-टैंकरों द्वारा अपना सीवेज बाहर निकलवाते हैं। यद्यपि ट्रैक्टर वालों को दाम तो इसे बहुत दूर यमुना में डालने के दिये जाते हैं परन्तु वे दूर जाने की बजाय आस-पास ही जहां-तहां अपने टैंकरों को खला देते हैं। वैसे यमुना नदी में डालना भी कोई अच्छी बात तो नहीं है, परन्तु और कोई व्यवस्था भी तो सरकार ने नहीं बनाई है। पूरे शहर का सरकारी सीवेज भी तो गुड़गांव नहर, आगरा नहर व यमुना नदी में ही तो जाकर गिरता है।

सोसायटियों की यह समस्या कोई एक दिन में यकायक पैदा नहीं हो गयी। इसे सरकार ने ही कई बरसों में धीरे-धीरे पैदा किया व पनपाया है। कोई भी सोसायटी यकायक अपने आप से बन कर खड़ी नहीं हो गयी है। इसके लिये सरकार ने बाकायदा लाइसेंस जारी किये हैं। सीएलयू जारी करके कृषि से रिहायशी क्षेत्र बनने दिया है। जाहिर है इन सबके बदले शासकों ने मोटी फ़ीस व अधिकारियों ने मोटी रिश्वतें ली हैं।

इसके अलावा प्रत्येक सोसायटी से मनमानी मोटी दरों पर ईडीसी (बाहरी विकास खर्च) भी वसूल की है। इस ईडीसी का मतलब सोसायटी की अन्दरूनी सड़कों व सीवरेज को बाहरी सड़कों व गहरी सीवर लाइन से जोड़ना होता है। इसके लिये सरकार बाकायदा भूमि अधिग्रहण करके सड़कों व गहरी सीवर लाइन का निर्माण कराती है। परन्तु दसियों बरस पहले सरकार ने ईडीसी के नाम पर हज़ारों करोड़ तो वसूल कर डकार लिये परन्तु बाहरी मुख्य सड़कें व सीवर लाइनें डालने का अपना दायित्व नहीं निभाया।

हो सकता है किसी सोसायटी ने ईडीसी जमा न कराई हो, तो इसके लिये सोसायटी में बसे निवासी जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिये सोसायटी बनाने वाला तथा वे सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिना ईडीसी वसूले सोसायटी का निर्माण होने दिया व उसमें लोग़ों को बसने दिया। इसके लिये सोसायटी के निवासियों को कतई दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रदूषण विभाग के नोटिसों को लेकर वहां के खौफजदा निवासी ज़िले के उपायुक्त से मिले तो उन्होंने इसे अदालती मामला कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया। वैसे अदालती कार्यवाहियों का ड्रामा भी इन सोसायटियों को लेकर काफ़ी हो चुका है। परन्तु अदालतों के कठोर निर्णयों की जगह लचर-पचर फ़ैसलों के चलते जनता को कोई विशेष राहत नहीं मिल पाती।

अभी कुछ माह पूर्व ही खुले में सीवरेज डालने के मामले को लेकर लोग एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल) तक भी गये थे। वहां कई दिनों की ड्रामेबाज़ी के बाद सोसायटी निर्माता बिल्डरों पर कुछ जुर्माने लगा कर मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया। मामले की तह तक जाकर समस्या का जड़-मूल से निवारण करने की कोई नहीं सोचता।

आज के जमाने में यह कितना अज़ीब लगता है कि लाखों की आबादी का एक शहर ग्रेटर फ़रीदाबाद के नाम से सरकार बसा रही है जिसमें सीवरेज की व्यवस्था ही नहीं है। सीवरेज व्यवस्था करने के नाम पर जो पैसे सरकार ने वसूले थे उन्हें तो डकार गयी और लोग़ों को बिना सीवर व्यवस्था के बसने दिया गया। इसमें दोषी तो शासक वर्ग के वे सब लोग हैं जिन्होंने यह सब किया है। क्या इनके विरुद्ध कोई ट्रब्यूनल कड़ी कार्यवाही कर पायेगा?